it and I take the full responsibility on it. I have got documents

MR. SPEAKER: There is no question of taking responsibility The question asked is replied to by him If there is anything else, that is a different matter.

SHRI JYOTIRMOY BOSU They are fully in the know how to bypass the rules and laws They used the industrial hardware as dummy

MR SPEAKER. This cannot arise out of this

SHRI JYOTIRMOY BOSU They used this as dummy They cannot trespass the conditions in letter or in spirit.

SHRI T A PAI So far as I am concerned, I strongly deny the allegation that we have done anything wrong in helping the Maruti to get anything imported But, I am unable to answer every allegation because it looks as if we can furnish any information that is called for

SHRI JYOTIRMOY BOSU I am sure the Minister is misleading the House

SHRI R S PANDEY May I know when is Maruti car coming in the market? I have read about it in the newspapers

MR SPEAKER That does not arise out of this

SHRI R S PANDEY May I know when is it coming?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मुझे अखबारों में पढ़ने को मिला था कि मारूती कार के एक मालिक को प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अपने पद से इस्तीफा दे दीजिये, क्यों कि सरकार की बदनामी होती है । मंत्री जी को इसके बारे में जवाब देना चाहिये ।

SHRI T. A. PAI: An industrial licence is given to a company Who manages it, who resigns and who comes, it is not my affair. I am unable to furnish such information.

आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

*658. श्री जनेश्वर मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों आकाशवाणी के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव पद के लिये उम्मीदवारों का चयन किया गया था ,

(ख) यदि हां, तो कितने तदर्थ प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों ने उक्त पद के लिये आवेदन पत्र दिये थे, उनमे से कितनों को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था और आयोग ने इनमे से कितने उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया था ,

(ग) आयोग द्वारा इस पद के लिये अस्वीकार किये गये व्यक्ति पिछले कितने वर्षों से दिल्ली मे कार्य कर रहे थे, और

(ख) क्या पाच वर्ष से अधिक समय से दिल्ली मे काम कर रहे व्यक्तियों का निकट भविष्य मे तबादला किया जायेगा और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) 139 तदर्थ प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पद के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे। इनमे से 34 का चयन किया गया है । चूंकि इन्टरव्यू आयोग द्वारा लिए जाते है, इसलिये इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे मे सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दिल्ली मे विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत जिन तदर्थ प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों ने संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन-पत्र भेजे थे और जिनका नियुक्ति के लिये चयन नहीं हुआ, वे किसी न किसी रूप में 9 महीने से लेकर

15 वर्ष तक भिन्न भिन्न अवधियों के लिये दिए जा रहे हैं।

(घ) स्थानान्तरण आवश्यक रूप से किसी विशिष्ट केन्द्र पर काम करने की अवधि के आधार पर नहीं किये जाते। कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखा या स्थानान्तरित किया जाता है।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विरोध पक्ष की तरफ से जो यह शिकायतें आती रहती हैं कि रेडियो में, खास तौर पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के एपाइन्टमेंट के बारे में कि पिछले दो साल में उनके पदों पर जो प्रमोशन हुआ है, क्या वह भी संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ है या सरकार ने मनमाने ढंग से अपनी मर्जी के लोगों को, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, प्रमोट किया है ? क्या बाकी के जो दूसरे लोग इसके लिये उपयोगी और काबिल थे उनको प्रमोट नहीं किया गया है ? क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवस् की तरफ से कई बार इसके बारे से ज्ञापन भी सरकार को मिले हैं ? मंत्री महोदय का इस बारे में क्या जवाब है?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I K GUJRAL) Sir, first of all I would like to strongly refute the implied allegation of the hon Member regarding governmental policy Sir so far as the position regarding Programme Executives is concerned it has been decided that 50 per cent of the Programme Executives would be selected directly by U.P.S.C and the remaining 50 per cent through promotion by D P C These rules have been approved by the Department of Personnel and also by the concerned departments In this connection I may say that only recently a selection has taken place and fortunately the U.P.S.C has selected a number of people from various areas and languages which were not represented in All India Radio before.

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं।

मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि यह जो इनकी प्रमोशन की गई है, इसमें भी क्या संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश आई थी, या इस मंत्रालय ने या इस महकमे ने मनमाने ढंग से प्रमोशन कर दिया है ? मंत्री जी इस बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं।

SHRI I K GUJRAL. For Class II promotions U.P.S.C representative as a matter of rule was not associated but the D P C which was constituted internally associated somebody from outside For Class I promotions U P S C Member is associated

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने सवाल यह पूछा था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवस् के जो ट्रांसफर किये जाते हैं, उनमें बहुत से ऐसे एड-हाक एपाइन्टीज हैं जिनके कई सालों से ट्रांस्फर नहीं हुए हैं और कई सालों से यहां पड़े हुए हैं और वह किसी भी कम्पीटीटिव एक्जाम में कंपीट नहीं कर पाये हैं, जिनकी वजह से दूसरे काबिल लोग वहां काम पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये लोग सरकार की मर्जी पर दिल्ली में पड़े हैं। क्या इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की तरफ से आया है कि बहुत से लोग बड़े अफसरों और मिनिस्टरों की मर्जी से यहां पड़े हुए हैं क्योंकि ट्रांसफर से बहुत धांधली और मनमानी हो रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : आनरेबल मेम्बर ने शायद इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जब ट्रांस्फस वगैरह की जाती हैं—किसी को यहां रखा जाये या बाहर भेजा जाये—, तो मकसद यही होता है कि किस तरह रेडियो का काम बेहतर चल सकता है। सरकार के हर महकमे में यही बात होती है। ऐसी कोई धांधली हमारे नोटिस में नहीं आई है, और अगर आयेगी, तो उस के बारे में एक्शन लिया जायगा।

SHRI S. M BANERJEE. Sir, the hon. Minister has said that the service conditions of these employees are governed by the rules which have been

framed by the Department of Personnel. I would like to know from the hon. Minister whether the All India Radio employees are Central Government employees or Corporation employees? What are they? Whenever service rules are made applicable, they say that they are Central Government employees. When it comes to the question of salary, they are not Government employees. I would like to know, when is a final decision going to be taken about the service conditions of these employees? I would like to know whether they are Central Government employees or Corporation employees?

SHRI I K GUJRAL: I may say that all the programme executives in the All India Radio are Government servants

SHRI S M BANERJEE Only programme executives. What about others?

SHRI SAMAR GUHA Sir, I was trying to draw the attention of the hon Minister several times about this promotion matter I am glad to know that at least promotions to the extent of 50% will be made on the basis of the recommendation of the UPSC What about the other 50%? This departmental promotion depends mainly on the confidential reports on the performance of the officers in different stations I have also brought to the notice of the hon Minister that in sending such confidential reports, subjective factors are introduced Even good officers are not always given good certificates by their superiors That creates a problem. This has created problems in many other cases to which also I have drawn the attention of the hon Minister. I would like to know from the hon. Minister whether this dependence on the confidential reports by station directors will be done away with and some other independent method will be introduced so that subjective factors in the matter of promotions may not interfere with the merit of any candidate?

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend has opened a very much broader issue, regarding the confidential reports I share most of his observations. I do feel that a more scientific system is needed for assessment of the performance of the officers not only in All India Radio, but, in other Ministries of the Government of India as well. But, unfortunately, up till now, no alternative system has been devised. We go on following the same confidential report system. I hope a more scientific system will be introduced soon. I am told, the concerned Ministry is giving attention to this.

देश में संकटकालीन स्थिति

*659. श्री हेमेन्द्र सिंह बघेरा :
श्री एस० एम० सिंघ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1974 को प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश में वर्तमान आर्थिक समस्याओं के कारण संकट-कालीन स्थिति को चालू रखा जा रहा है;

(ख) वर्तमान संदर्भ में उन कारणों का औचित्य क्या है जो कि संकटकालीन स्थिति लागू करते समय बताये गये थे, और

(ग) क्या 1962 में घोषित संकटकालीन स्थिति जिस समय समाप्त की गई थी, आज उससे बढ़कर बाह्य आक्रमण का खतरा है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 15 जून, 1974 को विदेशी पत्रकार संघ के साथ संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने केवल कठिन आर्थिक स्थिति, जो युद्ध के समय में स्थिति के समान गम्भीर थी, का उल्लेख किया था।

(ख) संकट कालीन स्थिति की घोषणा को जारी रखने के लिए देश की सुरक्षा अपेक्षाओं पर अत्यधिक निर्णायक विचार किया जाता है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा के खतरे के संबंध में 3 दिसम्बर, 1971 को की गई थी। यह खतरा जारी है।

(ग) जनवरी, 1968 और इस समय की स्थिति के बीच कोई तुलना करना अर्थपूर्ण